भारत में विमुद्रीकरण के नीतिगत उद्देश्य एवं चुनौतियाँ

डा0 जोगिन्द्र सिंह,
विभाग : राजनीति विज्ञान,
गाँव – भगवतीपुर (रोहतक)

शोध सार– सत्ता में आने के बाद बहुत जल्दी प्रधानमंत्री 'नरेन्द्र मोदी' ने संकेत दे दिया था कि वे सुनियोजित ढंग से काले धन की अर्थव्यवस्था को पुरस्कार व दंड की नीति से घटाने के लिए कदम उठाएंगे। इस दिशा में पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार ऐसी कई योजनाएँ लाई है। इसमें काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी), जनधन व मुद्रा बैंकिंग और ई–भुगतान के लिए सीधे लाभ,प्रोत्साहन योजनाएँ और काला धन घोषणा करने की योजना शामिल है। जैसा कि एक लोकप्रिय हैडलाइन में कहा गया,'कैश इज नो लॉन्गर किंग'यानी नकदी अब सर्वप्रमुख नहीं है। प्रधानमंत्री 'नरेन्द्र मोदी' ने पांच सौ व हजार की मौजूदा करेंसी नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया। यह जो विमुद्रीकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार महंगाई,हवाला करोबार,आतंकवाद में फंडिग,जाली नोट से निजात पाना और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम कसना है।

मूल शब्द–बैंकिंग,मुद्रा,अर्थव्यवस्था,आतंकवाद,भ्रष्टाचार,काला धन,महंगाई,चुनाव,इलैक्ट्रोनिक।

माननीय प्रधानमंत्री'श्री नरेन्द्र मोदी' का यह कदम दो प्रकार के काले धन को निशाना बनाता है। एक,सीमा पार से भेजे फर्जी नोट । दो,कर चोरी करने वालों द्वारा नकदी और संपत्ति के रूप में जमा धन।फर्जी करेंसी का आतंक को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल आतंकी गुट 70 करोड़ रूपए। अर्थव्यवस्था में डालते हैं और इसमें से सिर्फ 20.25 करोड़ रुपए ही पकड़े जाते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा 1000 रुपए के नोट होते हैं। एक हजार का एक नोट छापने में आतंकी गुटों को 39 रुपए खर्च आता है। इसका उपयोग वे अपने गुर्गों के माध्यम से खरीद में करते हैं और इस प्रकार हर नोट पर 961रुपए का लाभ कमाते हैं। काला धन अल्पावधि में गुप्त जगहों पर बोरी में छिपाए नोटों के रूप में दीर्घावधि के लिए अचल संपति में निवेश करते हैं। अब गुप्त जगह छपाए नोटों की कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि नोट चलन के बाहर कर दिए गए हैं। दीर्घावधि निवेश की बात करें तो संपत्ति आमतौर पर सफेद और काले धन के मिले–जुले स्वरूप में (कुछ चेक से और कुछ नकद) खरीदी जाती है। अब प्रधानमंत्री के कदम से नया चक्र शुरू होगा। इसमें सिर्फ नया काला धन निर्मित हो सकता है। यदि प्रापर्टी बेचने वाला कुछ सफेद और कुछ काले धन की मांग करता है तो खरीददार को सफेद धन बैंक में इस्तेमाल करके काले धन में बदलना होगा। लेकिन खरीददार ऐसा सौदा तब तक नहीं करेगा जब तक उसे प्रोपर्टी की कीमतों में गंभीर वृद्धि अपेक्षित न हो।

शोध–प्रविधि:इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गई हैं। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों,पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

इस तरह काले धन के दोगुने–चौगुने होने का दुश्चक्र बंद हो गया है,जिससे उन सामान व सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी,जिसे आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बैंकिग तथा कर के

दायरे में लाते हुए कैशलैस अर्थव्यवस्था की राह बनाना भी है। किसी भी देश का समुचित विकास तभी संभव है, जब वहा मुद्रा का आदान–प्रदान और अनवरत प्रवाह स्वतंत्र बैंकिग प्रणाली के माध्यम से ही हो। अगर किसी प्रकार कहीं समानांतर अर्थव्यवस्था का किसी भी रूप में अस्तित्व है तो तरक्की मुश्किल हो जाती है।

यद्यपि,इस कठोर निर्णय से 15 दिनों तक आमजन को परेशानी होगी,जो हम पिछले हफ्ते से देख ही रहे हैं,पर लंबी अवधि के हिसाब से यह गेम चेंजर फैसला साबित होगा,जो देश को एशिया ही नहीं विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था में शामिल कर सकता है। देश के शेयर बाजार में भी शुरुआती उठापटक के बाद तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। ज्यादातर बैंकिग कंपनियों में तो दस प्रतिशत से ज्यादा का उछाल देखा गया। साफ संकेत है कि देश की बैंकिग व्यवस्था के साथ विकास दर में वृद्धि होगी व साथ ही महंगाई,आतंकवाद व कालाबाजारी जैसी गंभीर समस्याओं से निजात मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी बॉन्ड व ब्याज दरों में गिरावट आएगी,प्रापर्टी के भावों में कमी आने की संभावनाएँ बन रही हैं,सोने व अन्य अमूल्य धातुओं की खरीददारी पर भी लगाम लगेगी। देश में इन्वेस्टमेंट और व्यापार के तौर–तरीके में बदलाव भी आएगा। शेयर बाजार,म्युचुअल फंड,इंश्सोरेन्स व अन्य टैक्स फ्री बॉन्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा।

देश में प्रचलित साहुकारी ब्याज,कच्चे व पक्के की असमानता पर रोक के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक के मार्फत लेन–देन व पेन कार्ड हासिल कर आय–व्यय के ब्यौरे का रिटर्न फाइल करने की तरफ बढ़ेंगे।

इस फैसले का एक अन्य पहलू हैं। उत्तरप्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव । सरकार की मुदा परिवर्तन की नीति से लगता है कि भाजपा के अलावा अन्य सभी दलों के पास नई करेंसी की कमी होने की वजह से उनका चुनाव प्रचार कुछ ढीला पड़ सकता है। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च होने वाली राशि पर सख्ती उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर पर भी लगाम लगाने पर मजबूर कर देगी। हालांकि,इसका एक सकारात्मक प्रभाव चुनाव में होने वाली पैसे की बर्बादी को कम करने में जरूर देखने को मिल सकेगा। इसी प्रकार 'मोरारजी देसाई' ने भी1978 में नोट बंद किये थे। उनसे जब पूछा गया कि इतना कठोर कदम उन्होंने क्यों उठाया तो रूखा जवाब था। श्रीमती गांधी को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि वे मानते थे कि चुनाव में खर्च करने के लिए उनके पास बड़े करेंसी नोटों की थपियाँ हैं। लगभग 40 साल बाद एक और प्रधानमंत्री ने भी कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव के ठीक पहले पांच सौ और हजार रूपए के नोट बंद किए हैं। मोरारजी की कार्यवाही ने कुल करेंसी के 1 फीसदी को चलन के बाहर किया। इस बार के कदम ने तो 80 फीसदी करेंसी को बाहर कर दिया।

सरकार को उम्मीद थी कि 500/1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने से कालेधन का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी में वापस नहीं आएगा। लेकिन तीन हफ्ते बाद इस उम्मीद पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिसम्बर तक लोग बैंकों में 12.6 लाख करोड़ रुपए जमा करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया तो रिर्जव बैंक के डिप्टी गर्वनर आर0 गांधी ने बताया था कि देश में 500 रुपए के 16.5 अरब और 1000 रुपए के 6.7 अरब नोट चलन में हैं। यानी इनकी कुल वैल्यू 14.95 लाख करोड़ रुपये थी। सूत्रों के अनुसार,ऐसा लगता है कि नकद कालेधन को लेकर सरकार का अनुमान गलत साबित होगा। सरकार का आकलन था कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे। अर्थशास्त्री भी इसे सरकार के लिए विंडफॉल के रूप में देख रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस राहत पैकेज की चर्चा थी, वे सम्भावनाएँ कम होती नजर आ रही हैं।

नोटबंदी की निम्न आधारों पर आलोचना हो रही है–

- पांच सौ और एक हजार रुपए का नोट बंद करके दो हजार का नोट क्यों लाया गया है,इससे भ्रष्टाचार अधिक पनपने की आशंका है।
- 2 लाख 35 हजार ए0टी0एम0 में नये 2000 और 500 के नोटों का सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया,जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पडा।
- नकदी के अभाव में रोजगारी पर काम करने वाले श्रमिक और छोटे व्यापारी मुश्किल में आ गए। इस कारण वर्तमान समय में निचले तबके को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ए0टी0एम0 के सामने लंबी कतारें देखने को मिली।
- किसान जो पैसा अपने पास रखते थे,जिनके बैंक में खाते नहीं थे उन्हें पैसा जमा करवाने के लिए कठिनाई आ रही हैं और निकासी के लिए उससे भी बड़ी समस्या बनी।
- नोटबंदी ने नए किस्म के मुद्रा–दलालों को जन्म दिया है,जो पुराने नोट 30 से 40 फीसदी के डिस्काउंट पर बदल रहे हैं। चूंकि सरकार कालेधन के खिलाफ बेमानी जमीनों की जांच जैसे और अधिक कठोर कदम उठाने की धमकी दे रही है,लोगों का झुकाव किसी नए माध्यम से पुराने कालेधन को नए कालेधन में बदलने का है।

इनके बावजूद भी छियासी फीसदी नकदी को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम को तत्काल सफलता या विफलता के खांचे में नहीं रखा जा सकता। आकलन कुछ माह बाद ही हो सकेगा। इसे लागू करने का मोदी जी का मूल आधार कालेधन के खिलाफ संघर्ष छेड़ना है। किंतु भारतीय रिजर्व बैंक के 'पूर्व गर्वनर रघुराम राजन' सहित कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ''ऐसी काली कमाई करने वाले या तो उन्हें छोटे डिपॉजिट में बांट देते हैं या व्यवस्था में ही कोई तरीका खोज लेते हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''कालेधन का बड़ा हिस्सा नकदी सोने में संग्रहित किया जाता है या पहले ही उसका रियल एस्टेट में पुनर्निवेश किया जा चुका होता है।''

हालांकि,विशेषज्ञों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। यह कदम काले धन का लेन–देन रोकने के लिए अच्छा है,क्योंकि इससे संबंधित लोगों को भुगतान के 'कम नकदी वाले,जोखिम भरे' तरीके खोजने होंगे और ऐसे भुगतान की पहचान आसान हो जाएगी। भारत की कर दरें दुनिया में सबसे कम हैऔर सिर्फ 3 फीसदी भारतीय टैक्स भरते हैं यानी इस मोर्चे पर हमारी व्यवस्था दयनीय रूप से नाकाम रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री 'श्री नरेन्द्र मोदी' ने सही संघर्ष छेड़ा है,लेकिन उन्हें इसमें और भी कई मोर्चे खोलने होंगे। केन्द्र सरकार का यह कदम सचमुच में रंग लाता यदि नए नोटों पर सैटेलाइट से ट्रैक हो सकने वाली 'नैनो चिप' होती,जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति बड़ी मात्रा में पैसे का लेन–देन बिना निगरानी में आए न कर पाता। इससे कालेधन,आतंकवाद,भ्रष्टाचार,महंगाई पर अधिक रोक लगती और देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती।

संदर्भ सूची

- टाईम्स ऑफ इंडिया, 9 नवम्बर, 2016,पृ0 1
- हिन्दुस्तान टाईम्स, 9 नवम्बर, 2016,पृ0 1
- दैनिक ट्रिब्यून, 11 नवम्बर, 2016,पृ0 8
- दैनिक भास्कर, 11 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- हिन्दुस्तान टाईम्स, 11 नवम्बर, 2016,पृ0 10
- दैनिक भास्कर, 12 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- टाईम्स ऑफ इंडिया, 12 नवम्बर, 2016,पृ0 12
- हरि भूमि, 12 नवम्बर, 2016,पृ0 8
- दैनिक भास्कर, 15 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- दैनिक भास्कर, 16 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- दैनिक भास्कर, 19 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- दैनिक ट्रिब्यून, 24 नवम्बर, 2016,पृ0 8
- दैनिक भास्कर, 24 नवम्बर, 2016,पृ0 4
- टाईम्स ऑफ इंडिया, 24 नवम्बर, 2016,पृ0 12
- टाईम्स ऑफ इंडिया, 29 नवम्बर, 2016,पृ0 12
- दैनिक भास्कर, 29 नवम्बर, 2016,पृ0 5
- दैनिक ट्रिब्यून, 9 दिसम्बर, 2016,पृ0 1
- दैनिक ट्रिब्यून, 13 दिसम्बर, 2016,पृ0 8